# प्रेस समाचार

जनसंपर्क विभाग
अमेरिकी दूतावास

शांतिपथ, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021 दूरभाष: 011-24198000 एक्सटेंशन: 8827 फैक्स: 011-24198817
ईमेल: mpl@pd.state.gov इंटरनेट वेबसाइट: http://usembassy.state.gov/delhi.html

23 मार्च, 2006


## भारत में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू करने हेतु अमेरिकी सरकार और जनरल इलैक्ट्रिक ने हाथ मिलाए

नई दिल्ली -- एक महत्वपूर्ण प्रयास के अंतर्गत ग्रामीण भारत में हजारों लोगों को बिजली प्रदान करने हेतु अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ( यूएसएड ) और जनरल इलैक्ट्रिक कंपनी ( जीई ) ने पुनर्चक्रीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का कल आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया।

इस अनोखी सार्वजनिक-निजी साझेदारी का शुरुआत इस वर्ष के शुरू में वाशिंगटन में 26 जनवरी को की गई थी। इसके अंतर्गत भारत के विकास की सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण आवश्यकता को समझने हेतु अमेरिकी विशेषज्ञ तथा प्रौद्योगिकी प्रदान की जाएगी।

जनरल इलैक्ट्रिक द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कल अमेरिकी उपराजदूत रॉबर्ट ओ. ब्लेक ने कहा, ''नई दिल्ली में केवल तीन सप्ताह पहले राष्ट्रपति बुश तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ऊर्जा सहयोग सहित दोनों देशों के बीच रिश्तों को और बढ़ाने का संकल्प व्यक्त किया है। भारत में अमेरिकी मिशन को सार्वजनिक-निजी साझेदारी के माध्यम से ग्रामीण भारतीयों की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के नए प्रयासों में सम्मिलित होने पर गर्व है।''

जीई इन्फ्रास्ट्रक्चर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व अध्यक्ष श्री फर्डिनांडो 'नैनी' बेक्काली-फाल्को ने अपने संबोधन में कहा, ''यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम 2012 तक 'सभी के लिए विद्युत' उपलब्ध कराने की भारत सरकार योजना में सहायता करने की जीई की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। चार वर्ष पहले मेरे सहकर्मी जॉन राइस ने इस महत्वपूर्ण योजना में जीई के सहयोग की प्रशंसा की थी। अब यूएसएड के साथ कार्य करते हुए हम उस प्रशंसा को मूर्त्त रूप दे रहे हैं।''

कार्यक्रम में यूएसएड के ग्लेन व्हेली तथा एस. पद्मनाभन; जीई एनर्जी के जनरल मैनेजर ग्लोबल मार्केटिंग डेविड स्लम्प; एमपीपीपीएल के अध्यक्ष के. कृष्णन तथा भारतीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

यूएसएड इस कार्यक्रम के लिए 6,00,000 डालर ( छह लाख डालर ) का योगदान करेगा, जबकि जीई तथा इसके विशेषज्ञों व साझेदारों का विश्व नेटवर्क प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से 27 लाख डालर का निवेश करेगा। इसे लागू करने वाले कर्नाटक एवं महाराष्ट्र पहले राज्य हैं। 2006 के मध्य में इसके शुरू होने उम्मीद है।

***